भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 841
जिसका उत्तर बुधवार 23 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

लघु और मध्यम उद्यमों को पेश आ रही चुनौतियां

841. श्री बी. के. हरिप्रसाद:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लघु और मध्यम उद्यमों को अपने लघु पैमाने और अपर्याप्त संस्थागत तंत्रों, पूंजी तक सीमित पहुँच और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के प्रति अल्प जागरूकता के कारण नए उत्पादन और नई प्रक्रियाएं विकसित करने में चुनौतियां पेश आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने सूचित किया है कि अपर्याप्त संस्थागत तंत्र, पूंजी तक सीमित पहुँच और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति अल्प जागरूकता और अनुपालन की वजह से नए उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने में लघु और मध्यम उद्यम अब भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इन चुनौतियों का निराकरण करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय औजार कक्षों और तकनीकी संस्थानों, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), कलस्टर विकास कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड केपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और जेडईडी (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट) प्रमाणन स्कीम आदि के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता जैसी अनेक स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****